प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

30.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

'' मुख्य समाचार''

- राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी से की मुलाकात–हिमाचल के विकास व जनकल्याण से संबंधित विषयों पर की चर्चा ।
- विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 58 हजार 8 सौ 30 करोड़ रूपए से अधिक का बजट ध्वनिमत से पारित–
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा– राज्य सरकार एंट्री टैक्स में करेगी युक्तिकरण–दूसरे राज्यों के लोगों को पास के माध्यम से एंट्री टैक्स में दी जाएगी छूट ।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एंट्री टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री को पुनर्विचार कर समाधान निकालने की दी सलाह।
- राज्य सरकार ट्रैक्टर मालिकों को चालान से बचाने के लिए बनाएगी नीति ।

राज्यपाल भेंट

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के विकास और जनकल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने 'नशा–मुक्त हिमाचल अभियान' और 'टीबी–मुक्त हिमाचल अभियान' जैसे महत्वपूर्ण पहलों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है, लोगों को प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में किसान और बागवान रसायन मुक्त कृषि पद्धति को अपना रहे हैं। उन्होंने इन पहूलों को और अधिक बढ़ावा देने और विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बीच राज्यपाल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को हिमाचल प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया

बजट पारित

प्रदेश विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 58 हजार 8 सौ 30 करोड़ रुपए का बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सदन में पेश हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 के पारित होने के साथ ही राज्य सरकार को इस राशि को खर्च करने की वैधानिक अनुमति मिल गई है।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले 21 मार्च को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया था, जिसका प्रारंभिक आकार 54 हजार 9 सौ 28 करोड़ रुपये था, लेकिन अब संशोधित रूप में इसे बढ़ाकर 58 हजार 8 सौ 30 करोड़ 66 लाख 70 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस बजट में स्पष्ट संकेत है कि राज्य की बड़ी राशि अनिवार्य खर्चों पर जाएगी, जबकि विकास कार्यों के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध रहेंगे। बजट दस्तावेजों के अनुसार अगले वित्त वर्ष में सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर 100 रुपये में से लगभग 20 रुपये ही विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। बजट पारित करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने पहली बार प्रदेश की वास्तविक वित्तीय स्थिति को जनता के सामने पारदर्शिता के साथ रखा है और वित्तीय अनुशासन अपनाते हुए बजट के आकार को कम किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार नीतिगत सुधारों के जरिए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है और आम आदमी व मिडल क्लास पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। कर्ज को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और राज्य की जीएसडीपी के आधार पर ही कर्ज लेने की सीमा तय होती है। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे, ताकि बिना जनता पर बोझ डाले संसाधन जुटाए जा सकें।

कटौती प्रस्ताव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार एंट्री टैक्स में युक्तिकरण करेगी और दूसरे राज्यों के लोगों को पास के माध्यम से एंट्री टैक्स में छूट दी जाएगी। विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से इस मामले को उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा

कि एंट्री टैक्स को लेकर सरकार पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार के साथ भी बात करेगी। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने पड़ोसी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स नहीं बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स में जो बढ़ौतरी हुई है वो एनएचएआई द्वारा एंट्री टैक्स को फास्ट टैग के साथ जोड़े जाने के कारण हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी गाड़ियों के लिए एंट्री टैक्स पर कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, जबकि बड़े वाहनों के लिए एंट्री टैक्स 40 रुपये बढ़ा है। इससे पूर्व मामला उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए भारी भरकम एंट्री टैक्स के कारण पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद पैदा हो गया है और इन राज्यों के लोग बढ़े हुए एंट्री टैक्स से नाराज हैं।

प्रश्नकाल

राज्य सरकार ट्रैक्टर मालिकों को चालान से बचाने के लिए अलग नीति लाएगी, जिससे उनकी आय में बढ़ौतरी होगी। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक भुवनेश्वर गौड़ की गैर मौजूदगी में विधायक चंद्रशेखर द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बरसात के दिनों में नदियां जहां–जहां नुकसान कर रही हैं, सरकार वहां ड्रेजिंग करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फिलहाल कुल्लू में पायलट आधार पर ब्यास नदी की ड्रेजिंग आरंभ की है और यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रेजिंग के लिए कुल 42 स्थान चिन्हित किए गए हैं और मनाली में ब्यास नदी की प्राथमिकता के आधार पर ड्रेजिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रैक्टरों को चालान के दायरे से बाहर करेगी। इसके लिए सरकार एक नीति मंत्रिमंडल में लाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत ऐसा तरीका तलाशा जाएगा जिसमें ट्रैक्टरों को पुलिस और माइनिंग के चालान से बाहर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रैक्टर मालिकों को माइनिंग नियमों में भी छूट देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केवल सिंह पठानिया और रणवीर सिंह निक्का ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे।

पैंशनर

प्रदेश पेंशनरज संयुक्त संघर्ष समिति ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी विभिन्न लंबित वित्तीय देनदारीयो को अदा ना करने के विरोध में आज शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने कहा कि सुक्खू सरकार ने पिछले एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेनानिवृत हुए पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर ग्रेच्यूटी और लीव इनकेशमेट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 13 प्रतिशत डीए, 44 महीने का एरियर और चिकित्सा बिलों की अदायगी भी अभी तक नहीं की गई है। पैंशनरों ने कहा कि अगर समय रहते उनके हक नहीं दिए गए तो वह सुक्खू सरकार खिलाफ आंदोलन तेज कर देंगे। इस बीच पेंशनरों के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनके सम्मान और हितों के लिए प्रतिबद्ध है और बजट की सीमा के भीतर रहते हुए पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी से की मुलाकात–हिमाचल के विकास व जनकल्याण से संबंधित विषयों पर की चर्चा ।
- विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 58 हजार 8 सौ 30 करोड़ रूपए से अधिक का बजट ध्वनिमत से पारित–
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा– राज्य सरकार एंट्री टैक्स में करेगी युक्तिकरण–दूसरे राज्यों के लोगों को पास के माध्यम से एंट्री टैक्स में दी जाएगी छूट ।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एंट्री टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री को पुनर्विचार कर समाधान निकालने की दी सलाह।
- राज्य सरकार ट्रैक्टर मालिकों को चालान से बचाने के लिए बनाएगी नीति ।